

अधिनियम के तहत प्राधिकरण। हालांकि, इस मामले में अदालत के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह है कि - क्या शिकायतकर्ता को रिपोर्ट की प्रति से वंचित किया जाना चाहिए?

(46) हम यह नहीं सोचते हैं। कारण सरल है। यह अधिनियम रिपोर्ट को गोपनीय नहीं मानता है। और हम कानून द्वारा खुले रखे गए क्षेत्रों में गोपनीयता को नहीं पढ़ेंगे। विधायिका ने 'रिपोर्ट' पर गोपनीयता का पर्दा नहीं रखा है, हमें लगता है कि याचिकाकर्ता एक प्रति का दावा करने का हकदार था। उसे दिया जाना चाहिए था। प्रतिवादीगण ने गलत तरीके से इसका खंडन किया है, हम निर्देश देते हैं कि वे इसे तुरंत देंगे।

(47) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:—

1. हम घटते मूल्यों के युग से गुजर रहे हैं। लोकपाल अधिनियम, 1996, जनता में लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए बनाया गया था। इसके प्रावधानों का अर्थ करते समय 'पाठ और संदर्भ' को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
2. इस अधिनियम में, निस्संदेह, यह प्रावधान है कि कार्यवाही कैमरे में रखी जाएगी। यह साक्ष्य के संबंध में एक सीमित गोपनीयता की भी परिकल्पना करता है। हालांकि, इसे शिकायतकर्ता और सार्वजनिक व्यक्ति से गुप्त नहीं रखा जा सकता है।
3. यह अधिनियम या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से भी लोकपाल की रिपोर्ट पर गोपनीयता का कोई आवरण नहीं लगाता है, परिणामस्वरूप इसकी सामग्री को शिकायतकर्ता या सार्वजनिक व्यक्ति से छिपाया नहीं जा सकता है। वे एक प्रति के हकदार हैं।

(48) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्धारित किया जाता है कि प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता को रिपोर्ट की एक प्रति देने से इनकार करने में गलती की थी। विवादित आदेशों को खारिज किया जाता है। रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे रिपोर्ट की एक प्रति तुरंत प्रदान करें, कोई लागत नहीं।

आर. एन. आर

1

माननीय न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और एन. के. सूद के समक्ष, जे.

विजय सोनी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

मुख्य आयुक्त, यू. टी., चंडीगढ़ और अन्य-उत्तरदाता

C.W.P. No. 16116 of 1999

11 मई, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-चंडीगढ़ लीज होल्ड ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग रूल्स, 1973-RI. 13-लीज होल्ड के आधार पर किसी स्थल का आवंटन-भूमि किराया जमा करने में लगभग 8 महीने की देरी-RI. 13 संपदा अधिकारी को अच्छे और पर्याप्त कारणों से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किराए के भुगतान के लिए छह महीने तक का समय बढ़ाने के लिए अधिकृत करता है-आवंटनकर्ता भुगतान करने में देरी के लिए अपनी स्थिति समझाता है-संपदा अधिकारी स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का कोई कारण बताए बिना अधिकतम दर यानी की 100% पर जुर्माना लगाता है -प्रतिवादीगण की कार्रवाई

मनमानी और असमर्थनीय-आवंटनकर्ता को 20 प्रतिशत का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए जुर्माना लगाने वाले विवादित आदेश जो अधिकतम दर यानी की 100% पर जुर्माना लगाता है को रद्द किया जाता है।

निर्धारित है कि 1973 के नियमों का नियम 13 संपदा अधिकारी को भूमि किराया जमा करने में छह महीने का विस्तार देने की अनुमति देता है। उस देरी के लिए, केवल @6% ब्याज लिया जाता है। वर्तमान मामले में, देरी छह महीने से थोड़ी अधिक थी। हालांकि, 100% का दंड लगाया गया है। हम यह पाते हैं कि कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और असमर्थनीय है। यह सच है कि विनियम 13 प्राधिकरण को विवेकाधिकार प्रदान करता है। लेकिन शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। यह अनियंत्रित नहीं है। प्रत्येक आदेश में कारण बताए जाने चाहिए। यह उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। अन्यथा, अदालत को कार्रवाई को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। 100% का जुर्माना लगाने वाला प्रतिवादीगण का आदेश पूरी तरह से मनमाना है।

(पैरा 10 और 11)

एस. एम. शर्मा, याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता

सुश्री अनीता शर्मा, अजय तिवारी की अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की अधिवक्ता

### निर्णय

(1) क्या चंडीगढ़ प्रशासन की जमीन का किराया जमा करने में एक साल से भी कम समय के लिए जुर्माना लगाने की कार्रवाई मनमानी और अनुचित है? यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस याचिका में विचार के लिए उत्पन्न होता है।

(2) याचिकाकर्ताओं को दुकान-सह-कार्यालय स्थल न. 130-131, सेक्टर 8-सी, चंडीगढ़ पट्टे के आधार पर 60 लाख रुपये के प्रीमियम (मूल्य) पर आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिफल राशि का 25 प्रतिशत भुगतान किया था। इसके बाद 21 मार्च, 1995 को आवंटन पत्र जारी किया गया। पत्र की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलमक P. 1 के रूप में प्रस्तुत की गई है। शेष राशि प्रीमियम का 75 प्रतिशत है जिसका वर्ष 1996, 1997 और 1998 के 10 मार्च को या उससे पहले तीन वार्षिक किश्तों में भुगतान किया जाना था। याचिकाकर्ताओं को रुपये की दर से वार्षिक भूमि किराया @ Rs 1,50,000 भी देना पड़ता था।

(3) ऐसा प्रतीत होता है कि 1998 की अवधि के दौरान भुगतान की जाने वाली तीसरी किस्त के भुगतान में कुछ देरी हुई थी। संपदा अधिकारी ने 27 अक्टूबर, 1998 को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को 10 प्रतिशत के जुर्माने के साथ प्रीमियम के भुगतान के लिए किश्त के कारण देय राशि जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को जुर्माना @100% के साथ बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश भी दिया। भुगतान 18 नवंबर, 1998 तक करने का निर्देश दिया गया था। आदेश की एक प्रति अनुलमक P.2 में है। आदेश से पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने मुख्य प्रशासक के समक्ष एक अपील दायर की। इसे 26 फरवरी, 1999 को खारिज कर दिया गया था। इस आदेश की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलमक P.3 में है। एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। इसकी आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। किश्त जमा करने में देरी के लिए 10 प्रतिशत के जुर्माने को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि, भूमि किराया जमा करने में देरी के लिए जुर्माने के संबंध में, एड्वाइसर ने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। आदेश की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलमक P.4 के रूप में प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रतिवादीगण की कार्रवाई जमीन का किराया जमा करने में लगभग आठ महीने की देरी के लिए जुर्माना @100% लगाना से मनमानी और अनुचित है। इन आधारों पर, याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं कि विवादित कार्रवाई को रद्द कर दिया जाए।

(4) सहायक संपदा अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से एक जवाब दावा दायर किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि नियम 13 जुर्माना लगाने के लिए प्राधिकरण को अधिकृत करता है। कार्यवाई नियमों के साथ पुष्टि में है और इस प्रकार, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(5) पक्षों के वकील को सुना गया है।

(6) यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं को 10 मार्च, 1998 तक राशि जमा करनी थी। चूंकि जमा करने में देरी हुई थी, इसलिए संपदा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 27 अक्टूबर, 1998 के आदेश के माध्यम से, अवैतनिक भूमि किराए पर 100% की सीमा तक Rs 1,50,000.00 जुर्माना लगाया गया। क्या यह उचित था?

(7) चंडीगढ़ लीज होल्ड ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग्स रूल्स, 1973 का नियम 13 प्रासंगिक है। यह प्रावधान किया गया है कि प्रीमियम के अलावा, पट्टेदार 33 वर्षों की अवधि के लिए प्रीमियम के 2-XA% की दर से वार्षिक किराया का भुगतान करेगा। इस किराए का भुगतान सालाना देय राशि पर करना पड़ेगा। खंड (ii) का परंतुक संपदा अधिकारी को अच्छे और दूर्याप्त कारणों से नियत तिथि से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के आगे भुगतान पर किराए के भुगतान के लिए समय बढ़ाने के लिए अधिकृत करता है। इसके बाद, खंड (iii) निम्नानुसार प्रावधान करता है:—

“यदि नियत तारीख तक किराया का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पट्टेदार उस राशि के 100% तक के जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो 1973 के अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधित पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 8 में निर्धारित तरीके से लगाया और वसूल किया जा सकता है”।

(8) उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि चूक के मामले में पट्टेदार "देय राशि पर 100% से अधिक नहीं" दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(9) वर्तमान मामले में, प्राधिकरण ने बिना कोई कारण बताए अधिकतम दर पर जुर्माना लगाने का विकल्प चुना है। इसके अलावा, यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता नियमित रूप से किरत और भूमि किराया जमा कर रहे थे। उन्होंने प्रीमियम की राशि का 25 प्रतिशत भुगतान यानी Rs 15 लाख आबंटन पत्र जारी होने से पहले किया था। इसके बाद, पहली और दूसरी किरतों का भुगतान वर्ष 1996 और 1997 में किया गया था। यहाँ तक कि जमीन का किराया भी दे दिया गया था। इस अंतराल के दौरान, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया है, उन्होंने निर्माण किया था और इस प्रकार, एक बड़ी राशि खर्च की थी। उन्हें धन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। नतीजतन, वर्ष 1998 में राशि जमा करने में देरी हुई। नियत तिथि के लगभग एक महीने के भीतर, याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। उन्होंने जवाब दे दिया था। स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया था। 100% का जुर्माना लगाया गया था। मुख्य प्रशासक ने अपील को यांत्रिक रूप से खारिज कर दिया था। एड्वाइसर ने याचिकाकर्ताओं के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया और किरत जमा करने में देरी के लिए जुर्माने को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। हालाँकि, उन्होंने जमीन के किराए के संबंध में जुर्माने में कमी के लिए उसी स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया। क्यों? कोई कारण नहीं बताया गया। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण किरत जमा करने में देरी के संबंध में स्वीकार किया गया, तो इसे भूमि किराया जमा करने में देरी के संबंध में क्यों अस्वीकार कर दिया गया? इसका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा, यदि प्रीमियम की किरत जमा करने में देरी के मामले में 5 प्रतिशत की दर से जुर्माना पर्याप्त था, तो जमीनी किराए के मामले में जुर्माना @100% लगाना उचित क्यों माना गया? आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है।

(10) जहाँ तक भूमि किराए के भुगतान का संबंध है, नियम इसे किरतों के भुगतान से अलग तरीके से देखते हैं। नियम 13 संपदा अधिकारी को राशि जमा करने में छह महीने का विस्तार देने की अनुमति देता है। उस देरी के लिए केवल 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। वर्तमान मामले में, देरी छह महीने से थोड़ी अधिक थी। हालाँकि, 100% का जुर्माना

लगाया गया है। हम यह पाते हैं कि कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी है।

(11) यह सच है कि विनियम 13 प्राधिकरण को विवेकाधिकार प्रदान करता है। लेकिन शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। यह अनियंत्रित नहीं है। प्रत्येक आदेश में कारण बताए जाने चाहिए। यह उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। अन्यथा, अदालत को कार्रवाई को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान मामले में आदेश पूरी तरह से मनमानी है।

(12) परिणामस्वरूप, हम 100% का जुर्माना लगाने में प्रतिवादीगण के आदेश को रद्द कर देते हैं। मामले की परिस्थितियों में, हम संतुष्ट हैं कि 20 प्रतिशत का जुर्माना न्याय के उद्देश्यों को पूरा कर सकता था। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को 20 प्रतिशत का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। वे जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत पहले ही जमा कर चुके हैं। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी। उपर्युक्त अवधि के भीतर राशि वापस करने में विफलता के मामले में, याचिकाकर्ता जमा करने की तारीख से धनवापसी की तारीख तक 10 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ राशि के हकदार होंगे। देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(13) तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। इन परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

**आर.एन.आर**

*माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. सुधालकर के समक्ष, जे.*

*नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रमिक संघ (आर. ई. जी. डी.)-याचिकाकर्ता*

*बनाम*

*हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता*

*C.W.P. No. 7492 of 2000*

*5 अप्रैल, 2001*

*भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-श्रमिक संघ और प्रबंधन के बीच विवाद-तथ्य के प्रश्न-लिखित अधिकारिता-तथ्य के साक्ष्य के बिना प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर, हरियाणा